

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 23, 2019 (SRAVANA 1, 1941 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2019

संख्या टी/एपीपी/3/103/2671.— शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 27 की उप—धारा (1) तथा धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, कौशल विकास तथा उद्यम मन्त्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐच्छिक व्यवसाय में शिक्षुओं की नियुक्ति की देखरेख के लिए राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक, हरियाणा कौशल विकास मिशन को क्रमशः संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा तथा उप राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा के रूप में नियुक्त करते हैं तथा नीचे दी गई ऐसी शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित शिक्तयों को प्रत्यायोजित करते हैं, अर्थातः—

शक्तियों का प्रत्यायोजनः

- (क) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोन्नत योजना के अधीन विभिन्न क्षेत्रों / योग्यताओं से सम्बन्धित वैकल्पिक व्यवसायों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार प्रशिक्षुता की संविदाओं का अनुमोदन / रिजस्टर करना;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप—धारा (2), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उप—धारा (2) तथा 15 की उप धारा (2) के अनुसार तथा शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप—नियम (6), (7) तथा नियम 12 के उपनियम (2) के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोन्नत योजना सहित शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन कार्यकलापों को कार्यान्वित करना:
- (ग) राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 31 के अनुसार कार्यकलापों को कार्यान्वित करना:

शर्ते :

- (i) उनकी अधिकारिता केवल राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा की अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों में ऐच्छिक व्यवसायों की शिक्षुता / कौशल कार्यकलापों के लिए होगी;
- (ii) राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा, समय-समय पर, प्रत्येक तीन मास के पश्चात प्रगति की समीक्षा करेगा;
- (iii) नियुक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी;
- (iv) वे अपने वर्तमान परिलब्धियों के अतिरिक्त किसी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

देवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SKILL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

Notification

The 12th July, 2019

No. T/APP/3/103/2671.— In exercise of the powers conferred under sub-section (I) of section 27 and section 34 of the Apprentices Act, 1961 (Central Act 52 of 1961), the Governor of Haryana hereby appoints the Joint Director and Deputy Director, Haryana Skill Development Mission as Joint State Apprenticeship Advisor, Haryana and Deputy State Apprenticeship Advisor, Haryana respectively for looking after the engagement of apprentices in Optional trades as per the guidelines issued by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India and National Skill Development Corporation, under control of State Apprenticeship Advisor, Haryana and delegate the following powers subject to such conditions as given below, namely:-

Delegation of Powers-

- (a) To approve/ register contracts of apprenticeship as per provision of section 4 of the said Act for Optional trades pertaining to various sectors/qualifications under the National Apprenticeship Promotion Scheme.
- (b) To carry out the activities under apprenticeship training programme including National Apprenticeship Promotion Scheme as per sub-section (2) of section 7, sub-section (2) of section 8, sub-section (2) of section 9 and sub-section (2) of Section 15 of the said Act and as per sub-rule (6) and (7) of rule 11 and sub-rule (2) of rule 12 of the Apprenticeship Rules, 1992.
- (c) To carry out the activities as per section 30 and section 31 of the said Act with prior approval of State Apprenticeship Advisor, Haryana;

Conditions:-

- (i) They will have jurisdiction for apprenticeship/skilling activities for Optional Trades only in the establishments falling under jurisdiction of State Apprenticeship Advisor, Haryana;
- (ii) State Apprenticeship Advisor, Haryana shall review the progress periodically after every three months;
- (iii) The appointment shall be for two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette:
- (iv) They shall not be entitled for any kind of remuneration in addition to their present emoluments.

DEVENDER SINGH,

Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Skill Development and Industrial Training Department.